सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com

swarajindianews swarajindianews

दैनिक सांध्यकालीन

स्वराज इंडिया

कानपुर, शुक्रवार, 28 नवंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 317, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

मुजफ्फरनगर के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी: कपिल देव अग्रवाल

» Pg12

इनसाइड 11 दिन तक इंजीनियर दंपति 'डिजिटल अरेस्ट'... » Pg02

बांग्लादेश तक फैले फेन्सिडिल रैकेट का पर्दाफाश

पूर्वांचल के माफिया से जुड़े रहे सिरप सिंडिकेट के तार!

सौ करोड़ी नशा कारोबारी का पार्टनर अमित गिरफ्तार, दुबई से ऑपरेट कर रहा शुभम जायसवाल, लुक आउट नोटिस जारी

नकली दवा माफिया को बचाने वालों पर गहराता जा रहा संदेह

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ/वाराणसी। वाराणसी में नशीले और जहरीले कफ सिरप के अवैध कारोबार का जाल कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मासूम बच्चों की जान लेने वाले इस नेटवर्क के सरगना कानून के शिकंजे से लगातार बचते आ रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने नशीले कफ सिरप फेन्सिडिल की तस्करी करने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। इस केस में एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है, जो दुबई भाग चुका है। शुभम को पकड़ने के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है।

जांच में सामने आया कि शुभम जायसवाल और उसकी टीम ने झारखंड में फर्जी फर्में बनाईं और इनके जरिए नशीली फेन्सिडिल सिरप पूरे देश में भेजी जाती थी। इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक होती थी। फेन्सिडिल बनाने वाली कंपनी फेन्सिडिल ने इस सिरप का प्रोडक्शन इसलिए बंद किया था क्योंकि इसकी बिक्री में लगातार फर्जीवाड़ा हो रहा था। देश के पांच सुपर स्टॉकिस्ट में से दो फर्में शुभम जायसवाल के सिंडिकेट के नाम पर थीं, यानी नेटवर्क बेहद बड़ा और संगठित था। दुबई में बैठे शुभम ने वाराणसी, मुंबई और दुबई में करोड़ों रुपए की संपत्तियां बना ली हैं। यही नहीं, उसने आरोपी अमित सिंह टाटा को दो बार दुबई और पटाया की विदेश यात्रा भी कराई थी।

वायरल वीडियो ने बढ़ाई मुश्किलें

मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल

शिकंजे में अमित टाटा

इस बीच अमित सिंह टाटा और शुभम का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमित अपने साथियों के साथ एक युवक की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। वीडियो वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। शुभम की कुछ तस्वीरें बाहुबली नेता धनंजय सिंह के साथ भी सामने आई हैं, जिनकी जांच भी जारी है। इसी कार्रवाई में एक फॉर्चूनर गाड़ी बरामद हुई जिसका नंबर 9777 है। जानकारों का कहना है कि यह वही नंबर है जो पूर्व सांसद तथा माफिया धनंजय सिंह की लगभग हर गाड़ी पर दर्ज रहता है। इससे साफ है कि अमित सिंह टाटा और धनंजय सिंह के बीच करीबी संबंध रहे हैं।

चर्चाओं में यह भी है कि धनंजय सिंह, अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई बताते रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि जहरीला कफ सिरप बनाकर बच्चों की जान लेने वाले इस गिरोह का असली संरक्षण बड़े हाथों में था। गिरफ्तार अमित सिंह टाटा को एक बाहुबली का प्रत्यक्ष समर्थन मिला हुआ था। गिरोह का किंगपिन शुभम जायसवाल अब भी फरार है और कई सफेदपोशों की मदद से उसके विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि शुभम जायसवाल के संपर्क केवल अपराध जगत तक सीमित नहीं थे। वाराणसी के कुछ पत्रकारों पर भी संदेह है कि वे उसके प्रभाव में थे। आरोप है कि कई ने अपने चैनलों और संस्थानों तक शुरुआती खबरें पहुंचाने से परहेज किया। कुछ खबरों में तो शुभम का नाम तक हटा दिया गया, ताकि मामला दबा रह सके और कार्रवाई में देरी हो।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस खतरनाक सिंडीकेट को राजनीतिक, प्रशासनिक और मीडिया जगत से संरक्षण कौन दे रहा था? जब तक इन सरपरस्तों को चिन्हित कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक इस गहरे नेटवर्क की परतें खुल पाना मुश्किल है। नकली दवाओं के इस माफिया तंत्र ने न केवल कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि मानवता को भी शर्मसार किया है। अब आवश्यकता है कि पूरे नेटवर्क की जाँच निष्पक्षता से हो और उन सभी चेहरों को बेनकाब किया जाए जो बच्चों की मौतों के ये अदृश्य जिम्मेदार हैं।

नकली दवाओं का बड़ा गढ़ कानपुर भी!

नकली और नशीली दवाओं का बड़ा गढ़ कानपुर भी बन चुका है। बीते दिनों ड्रग एवं औषधि विभाग की मुखिया रोशन जैकब ने लखनऊ से चुपके से आकर टीम सहित बिरहाना रोड के पास छापा मारा था तो बड़े पैमाने पर धांधली मिली थी, नकली दवाओं का जखीरा मिला था, इस पर कानपुर के कई ड्रग विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी लेकिन यहां के असली खिलाड़ियों पर एक्शन नहीं लिया गया।

योगी सरकार का फरमान

कई विभाग कर रहे थे स्वीकार, नोटिस जारी कर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को अब नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाणपत्र!

» ढाका/नई दिल्ली, एजेंसी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड की जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के रूप में शामिल किए जाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को जारी निर्देश में साफ कहा है कि आधार कार्ड के साथ कोई आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म तिथि सत्यापन के लिए मान्य नहीं माना जा सकता। कई विभाग अभी भी गलती से आधार कार्ड को जन्म तिथि के सबूत के तौर पर स्वीकार कर रहे थे, इसे रोकने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।

यूआईडीएआई ने बीते 31 अक्टूबर 2025 को जारी अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि आधार में दर्ज जन्मतिथि प्राधिकरण द्वारा सत्यापित नहीं होती, इसलिए इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

पत्र में यह भी उल्लेख है कि कुछ विभागों द्वारा अब भी आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।

जिसे गंभीर मानते हुए शासन ने दोबारा स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में यह दस्तावेज जन्मतिथि प्रमाण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा। इस बाबत शासन ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभागों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं तथा किसी भी स्तर पर आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए।

महाराष्ट्र में भी यही नियम लागू

महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह का कड़ा फैसला लिया है। राज्य में देरी से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगस्त 2023 में हुए कानूनी संशोधन के बाद सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बने सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। इसका मकसद फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के जरिए होने वाले अवैध कामों पर लगाम लगाना है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब कौन से दस्तावेज चलेंगे?

- अस्पताल में जन्म हुआ हो तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या अस्पताल का आधिकारिक प्रमाण पत्र।
- घर पर जन्म हुआ हो तो स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- अन्य वैध दस्तावेज स्कूल का बॉना-फाइड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि (विभाग के नियम अनुसार)।

11 दिन तक इंजीनियर दंपति 'डिजिटल अरेस्ट', ठग ले गए 42.50 लाख

जेट एयरलाइंस के संस्थापक नरेश गोयल के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी, ऑनलाइन 'सुप्रीम कोर्ट' सुनवाई तक कराई

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला कानपुर के बर्रा थानाक्षेत्र में सामने आया, जहां सेवानिवृत्त इंजीनियर और उनकी पत्नी को ठगों ने 11 दिनों तक वीडियो कॉल पर बंधक बना रखा। उन्हें सीबीआई अधिकारी बनकर धमकाया गया और जेट एयरलाइंस के संस्थापक नरेश गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर 42.50 लाख रुपये ऐंठ लिए।

बर्रा के जूही कलां डब्ल्यू-2 स्थित शिवम इन्क्लेव के निवासी राजेंद्र प्रसाद सिंह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से जूनियर इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हैं। वह पत्नी के साथ रहते हैं, जबकि बेटा नोएडा में इंजीनियर है। राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 7 अगस्त को उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आया।

कॉल करने वाले ने पुलिस वर्दी पहन रखी थी और खुद को सीबीआई में तैनात आईपीएस अधिकारी बताया। ठग ने दावा किया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मुंबई में केनरा बैंक के एक फर्जी खाते में किया गया है, जिसका इस्तेमाल नरेश गोयल के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है। बताया गया कि इस मामले में उनके अलावा 238 लोग शामिल हैं। इसके

बाद ठगों ने उन्हें 11 दिन तक लगातार वीडियो कॉल पर रखकर किसी से बात करने से मना कर दिया और जांच के नाम पर सारी जमा पूंजी बताए गए खातों में ट्रांसफर करने का दबाव बनाया।

दबाव और भय के चलते इंजीनियर दंपति ने 11 से 21 अगस्त के बीच पांच ट्रांजैक्शन में कुल 42.50 लाख रुपये जमा करा दिए। इसमें 24 लाख रुपये मुंबई की एक कंपनी के खाते में और बाकी रकम विभिन्न खातों में आरटीजीएस की गई। 18 अगस्त को ठगों ने ऑनलाइन 'सुप्रीम कोर्ट' सुनवाई भी कराई, जिसमें वीडियो कॉल पर जज बनकर सवाल पूछे गए। जब इंजीनियर ने रकम लौटाने की बात कही तो उनसे वकील फीस के नाम पर और 1 लाख रुपये की मांग की गई। आर्थिक तंगी बताने पर ठग धधमकाने लगे। इसी बीच नोएडा में रहने वाले बेटे नितिन को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ। घर आकर पिता से बात की तो पूरा सच सामने आया। बेटे ने तुरंत साइबर सेल और पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई।

कोई भी जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाती। डर और भ्रम पैदा कर साइबर ठग भोले-भाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। मामले में संबंधित खातों की जानकारी जुटाई जा रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

दीपेंद्र नाथ चौधरी, डीसीपी दक्षिण

रोटावेटर की चपेट में आकर किसान की मौत

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के छतेनी गांव में गुरुवार देर शाम रोटावेटर की चपेट में आकर किसान छतेनी गांव निवासी शरीफ अहमद की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची। शरीफ अहमद गुरुवार शाम करीब 7.45 बजे अपने खेत की जुताई के लिए गए हुए थे। ट्रैक्टर गांव का ही जैलेंद्र चला रहा था। रोड से हटकर खेतों की तरफ जाते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर की चपेट में आकर शरीफ़ अहमद की मौके पर ही मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही देवीपुर चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मृतक की पत्नी जैतून, पुत्र सैफ अहमद, सलीम अहमद, कलीम अहमद का रो रो कर बुरा हाल था। प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है।परिजनों की तहरीर मिलने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर की पहली ट्रेन पहुंची, डिपो में उतारे गए कोच

जल्द शुरू होगा परिचालन परीक्षण, 974 यात्री क्षमता और 80 किमी घंटा रफ्तार से दौड़ेगी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर सीएसए से नौबस्ता के बीच चलने वाली पहली ट्रेन शहर पहुंच गई। गुजरात के सावली प्लांट में तैयार की गई तीन कोच वाली यह हाईटेक ट्रेन को विशेष ट्रेलर द्वारा रावतपुर स्थित डिपो लाया गया, जहां बड़े क्रेनों की मदद से इसे ट्रैक पर उतारा गया। इस कॉरिडोर में कुल 10 ट्रेनें लगाई जाएंगी, जबकि पहले कॉरिडोर के लिए सभी 29 ट्रेनें पॉलिटेक्निक डिपो में पहले ही पहुंच चुकी हैं।

नई ट्रेन ऊर्जा संरक्षण के लिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक, अत्याधुनिक प्रोपल्शन

डिपो में उतारे गए मेट्रो के कोच

सिस्टम और कार्बन-डाइ-ऑक्साइड सेंसर आधारित स्मार्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस है। यह प्रणाली ट्रेन में मौजूद यात्रियों की संख्या के हिसाब से एसी को नियंत्रित करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार के मुताबिक, तीन कोच वाली इस ट्रेन में 974 यात्री सफर कर सकते हैं और इसकी अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि इसे 80 किमी/घंटा की ऑपरेशनल स्पीड पर चलाया जाएगा।ट्रेन में इमरजेंसी इंटरकॉम, पैनिक बटन और इंटीग्रेटेड सीसीटीवी सिस्टम लगा है, जिससे जरूरत पडने पर यात्री सीधे ट्रेन ऑपरेटर से बात कर सकते हैं। जल्द ही इस ट्रेन का डिपो में परिचालन संबंधी परीक्षण शुरू होगा। इसके लिए डिपो में 33 केवी आग्ज़िलरी-कम-ट्रैक्शन सब-स्टेशन तैयार कर लिया गया है और सिग्नलिंग का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है।

कानपुर: निर्यातक गोरखपुर से समझेंगे घरेलू बाजार की नब्ज

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर के निर्यातक गोरखपुर से पूर्वांचल के बाजार की नब्ज समझेंगे। निर्यातकों की सहायता वहां पर लगने वाले ट्रेड करने वाला है। शहर के निर्यातक ट्रेड शो में शामिल होने जा रहे हैं। उनका मानना है कि टैरिफ के बाद पूर्वांचल की डोमेस्टिक मार्केट की नब्ज टटोलने का यह बेहतर मौका है। गोरखपुर में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक ट्रेड शो आयोजित होने जा रहा है।

इस ट्रेड शो से शहर से भी लेदर और टैक्सटाइल के निर्यातक शामिल होने जा रहे हैं। निर्यातकों का मानना है कि यह ट्रेड शो निर्यात बाजार के लिए तो जरूरी है ही इसके साथ ही पूर्वांचल के घरेलू बाजार की पसंद व कारोबार का तरीका समझने के लिए बेहतर मौका है। निर्यातक यह भी मान रहे हैं कि गोरखपुर में नेपाल के कारोबारियों से संपर्क हो सकता है। ऐसे में नए ऑर्डर के लिए यह ट्रेड शो इस समय बड़ी जरूरत बनकर आया है।ट्रेड शो पर सना इंटरनेशनल एक्जिम के एमडी डॉ. जफर नफीस ने बताया कि ट्रेड शो विदेशी व घरेलू बाजार को समझने का एक बड़ा जरिया होता है। टैरिफ के बाद निर्यातक घरेलू और वैश्विक दोनो ही तरह के खरीदारों के साथ अधिक से अधिक संपर्क करना चाहते हैं। ऐसे में गोरखपुर में लगने वाला यह ट्रेड शो निर्यातकों के लिए बड़ा मौका बन कर आया है। यही वजह है कि ट्रेड शो से शहर से लेदर और टैक्सटाइल दोनो ही सेक्टर के निर्यातक शामिल होने जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगने के बाद शहर के निर्यातक अपना घाटा पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वह घरेलू बाजार के ऑर्डर भी पूरे कर रहे हैं। शहर में लेदर सेक्टर से जुड़े दो दर्जन से अधिक निर्यातक हैं जिन्होंने टैरिफ के बाद से डोमेस्टिक ऑर्डर पूरे करने में जुट गए हैं। टैरिफ के बाद से निर्यातकों पर ऑर्डर मिलने की परेशानी खड़ी हो गई है। कई निर्यातक नए विदेशी बाजार को तलाशने की जुगत में हैं। ऐसे में उनका मानना है कि घरेलू ऑर्डर से युनिट्स के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जरूरी है। निर्यातकों का यह भी मानना है कि यदि उन्हें घरेलू ऑर्डर मिलते हैं तो इससे युनिट्स में काम कम होने का खतरा कम होता है।

केडीए में 10 करोड़ टेंडर लूट मामले में

भ्रष्ट अफसरों की बर्बादी तय!

लखनऊ की माया बिल्डर फर्म को संरक्षण देने वालों की हो रही पहचान

» जांच में यह साफ है कि यह घोटाला अकेले नहीं हुआ।

» इसमें टेंडर समिति,लिपिकीय स्टाफ, जूनियर अभियंता, कुछ वरिष्ठ अधिकारी,और भुगतान प्रक्रिया करने वाले कर्मचारी शामिल रहे

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। स्वराज इंडिया की ओर से किए गए लगातार खुलासों के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के भीतर छिपा 10 करोड़ रुपये का फायर फाइटिंग घोटाला अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है। महीनों तक फाइलें दबाने, फर्जी अनुभव पत्र को वैध दिखाकर ठेका दिलाने और करोड़ों की बंदरबांट करने वाले अफसर-कर्मचारियों की अब शामत आ चुकी है।

स्वराज इंडिया ने सबसे पहले इस पूरे मामले की परतें खोली थीं, जिसके बाद शासन ने सख्ती दिखाते हुए जांच आगे बढ़ाई। सीडीओ दीक्षा जैन की रिपोर्ट के बाद माया बिल्डर को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही अब मुख्य आरोपी अफसरों की सूची सामने आ चुकी है।

जांच में यह साफ है कि यह घोटाला अकेले नहीं हुआ

इसमें टेंडर समिति,लिपिकीय स्टाफ, जूनियर अभियंता, कुछ वरिष्ठ अधिकारी,और भुगतान प्रक्रिया करने वाले कर्मचारी सब शामिल थे। 10 करोड़ रुपये का यह खेल पूरी चैन की मिलीभगत से संचालित हुआ था।

स्वराज इंडिया लगातार इस घोटाले में छिपे चेहरों को उजागर करता रहा, और अब शासन भी उसी दिशा में बढ़ रहा है।

स्वराज इंडिया ने खोला घोटाले का काला अध्याय

हमारी टीम की पड़ताल में जिन नामों ने केडीए की साख को कलंकित किया, वे हैं–

पूर्व चीफ इंजीनियर डीसी श्रीवास्तव

इन्हीं के समय में नियम तोड़कर टेंडर दिया गया। फर्जी अनुभव पत्र को बिना जांच मान्य किया गया और योग्य फर्मों की आपत्तियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। यह पूरा खेल मिलीभगत के बिना संभव नहीं था।

पूर्व अधिशासी अभियंता आशु मित्तल

टेंडर पास होने के बाद गलत भुगतान कराने में इनकी सीधी भूमिका उजागर हुई है। जांच रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि आशु मित्तल ने भुगतान जारी करने में जानबूझकर नियमों की अनदेखी की।

आशु मित्तल के तबादले के बाद शेष भुगतान कराने का काम उपाध्याय ने पूरा किया। उनके हस्ताक्षर और नोटिंग अब जांच का सबसे बड़ा सबूत बन चुके हैं।

एक्सियन मनोज उपाध्याय

शासन के पत्र दबाए गए, सबूत मिटाने की कोशिश भी हुई

स्वराज इंडिया ने जब दस्तावेज उजागर किए, तब पता चला कि
8 मई 2023 और 13 फरवरी 2023 को शासन ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन केडीए के अंदर पत्र दबाकर बैठे रहे भ्रष्ट अधिकारी।
मामले को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई छिपी न रह सकी।
इस खुलासे के बाद शासन ने उस समय के वीसी और सचिव तक से जवाब तलब किया है।
स्वराज इंडिया के अनुसार, बहुत जल्द निलंबन,विभागीय कार्रवाई,और विजिलेंस जांच
जैसी कड़ी कार्रवाइयाँ सामने आएँगी।

राजकीय आईटीआई पाण्डु नगर में 29 नवम्बर को अप्रेंटिसशिप मेला

» कई प्रतिष्ठित कंपनियाँ होंगी शामिल

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। युवाओं को रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से राजकीय आईटीआई पाण्डु नगर में 29 नवम्बर 2025 को अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में देश की नामीङ्गिरामी कंपनियाँ प्रतिभाग कर रही हैं, जहां आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित किया जाएगा।अजय कुमार द्विवेदी मीडिया प्रभारी, राजकीय आईटीआई पाण्डु नगर ने बताया कि मेले में जिन प्रमुख कंपनियों की भागीदारी तय है, उनमें टाटा मोटर्स (लखनऊ), ग्रोज इंजीनियरिंग टूल्स (गुरुग्राम), वीसी मोटर्स महिंद्रा (कानपुर), शिवम स्प्रिंग (कानपुर नगर) तथा वंशल एंड वंशल (कानपुर नगर) शामिल हैं।आयोजकों के अनुसार, महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है, उनका चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रातः 09:00 बजे राजकीय आईटीआई पाण्डु नगर परिसर में अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हों।आईटीआई प्रबंधन ने बताया कि यह मेला युवाओं को उद्योगों से सीधे जोड़ने तथा कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे दर्जनों अभ्यर्थियों को बेहतरीन अवसर मिलने की उम्मीद है।

विधायक मैथानी ने गैर जमानती वारंट जारी होते ही किया समर्पण

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। मार्ग दुर्घटना में मौत से संबंधित 14 साल पुराने मुकदमे में वादी भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी के कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचने पर गुरुवार को सीजेएम सूरज मिश्रा ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस बात की जानकारी होते ही विधायक ने दोपहर बाद कोर्ट में समर्पण कर दिया। उनकी मांग पर कोर्ट ने वारंट निरस्त करते हुए दो जनवरी 2026 को गवाही के लिए कोर्ट आने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड के चमोली निवासी इंजीनियर पुनीत मोहन ढिमरी गीतानगर में किराये के मकान में रहते थे। नौ फरवरी 2011 को पुनीत टेंपो पर आगे की सीट पर बैठकर मालरोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में खराब बीटीएस सही करने जा रहे थे। इसी दौरान बेनाझाबर आकाशवाणी के पास पीछे से आ रहे टेंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में पुनीत की मौके पर ही मौत हो गई और चालक फरार हो गया था।

पुनीत के रिश्तेदार नवीननगर निवासी सुरेंद्र मैथानी ने स्वरूपनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने टेंपो चालक बेकनगंज के तलाक महल निवासी मुश्ताक अली को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई तब से मुकदमा लंबित चल रहा है।

मुकदमे में वादी सुरेंद्र मैथानी की गवाही होनी थी लेकिन बार-बार समन भेजने के बावजूद मैथानी गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। मुकदमा 14 साल पुराना होने के कारण कोर्ट ने गुरुवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस बात की जानकारी होते ही सुरेंद्र ने दोपहर बाद कोर्ट में समर्पण कर दिया जिस पर कोर्ट ने उन्हें 20 हजार रुपये का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया। आदेश दिया कि गवाही पूरी होने तक वह जब भी न्यायालय में बुलाया जाएगा हाजिर होंगे।

सुधीर कुमार की संदिग्ध मौत पर बिल्हौर में उबाल, लेखपालों ने किया कामकाज ठप

लेखपालों ने नई तहसील भवन पर दिनभर दिया धरना, मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर/कानपुर। यूपी के फतेहपुर जिले से पिछले दिनों एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुहा कस्बा के रहने वाले 25 साल के एक लेखपाल सुधीर कुमार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। सुधीर कोरी बिंदकी तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात था। मौजूदा समय में सुधीर की ड्यूटी एसआईआर में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगी थी। सुधीर कुमार की संदिग्ध मौत ने प्रदेशभर के राजस्व कर्मचारियों को झकझोर दिया है। मामले में अधिकारियों पर आरोप लगने और अब तक ठोस कार्रवाई न होने से नाराज़ बिल्हौर तहसील के सभी लेखपाल शुक्रवार को दिनभर नई तहसील भवन पर धरने पर बैठे रहे। दिनभर चले इस विरोध में कर्मचारियों ने प्रशासनिक संवेदनहीनता, बढ़ते दबाव और अमानवीय व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों बिल्हौर को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि 2024 बैच के लेखपाल सुधीर कुमार की शादी 26 नवंबर को तय थी। छुट्टी के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद उन्हें अनुमति नहीं मिली।एसआईआर ड्यूटी के दौरान एक बैठक में अनुपस्थित रहने पर उनके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई।

कर्मचारियों का आरोप है कि निलंबन के बाद अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक उनके घर पहुँचे और ड्यूटी पूरी न करने पर कठोर कार्रवाई यहां तक कि सेवा समाप्ति की बात कही। विवाह की तैयारियों और विभागीय दबाव के बीच मानसिक तनाव में चल रहे सुधीर ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। संघ के जिलाध्यक्ष मोहित सचान ने कहा कि परिवार और सहकर्मी इसे साधारण आत्महत्या नहीं बल्कि लगातार बने दबाव और अपमानजनक व्यवहार की उपज बता रहे हैं। वहीं तहसील अध्यक्ष जीतेन्द्र यादव व महामंत्री सुनील चौधरी ने कहा कि हम सभी दिवंगत लेखपाल के परिजनों के साथ हैं। न्याय नहीं मिला तो आगे की रणनीति तैयार कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सर्वेश यादव खण्ड मन्त्री, ललित रजक पर्व तहसील अध्यक्ष, रोहित उमराव, अंकित सिंह ईशा, हिना समेत दर्जनों लेखपाल मौजूद रहे।

संगठन की यह हैं प्रमुख मांगें

धरने के दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन में कई मांगे उठाई।

- मुख्य आरोपी अधिकारी का नाम एफआईआर में शामिल किया जाए।
- मृतक परिवार की माता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
- परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले।
- एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।
- अधिकारियों को अधीनस्थों से संवाद और संवेदनशील व्यवहार के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

धरने में भीड़ से घिरी रही नई तहसील की बिल्डिंग

सुबह से ही नई तहसील भवन पर लेखपालों की भीड़ जमा होने लगी। कर्मचारियों ने साफ कहा कि दोषी अधिकारियों पर नामजद कार्रवाई नहीं होती, मृतक परिवार को न्याय और सहायता मिले। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी स्वयं की रैंकिंग और लक्ष्य पूरा करने की दौड़ में अधीनस्थों पर बिना वजह दबाव बना रहे हैं, जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है।

बिल्हौर में एसआईआर फीडिंग में सर्वर डाउन ने बढ़ाई मुश्किलें

अधिकारियों-कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ी

दिन भर में कई बार सर्वर ठप होने के कारण एसडीएम का 50 फीसदी टारगेट पूरा नहीं हो पाया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। निर्वाचन आयोग की एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिफाइड रिवीजन) प्रक्रिया सर्वर की लगातार खराबी के चलते अधर में फंस गई है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का रिकॉर्ड जुटा तो रहे हैं, लेकिन अपलोडिंग के वक्त नेटवर्क और सर्वर साथ नहीं दे रहा। पोर्टल बार-बार ठप होने से फीडिंग का काम रेंगने लगा है। बीएलओ के मुताबिक एक-एक फार्म अपलोड करने में करीब 10 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है। फोटो स्कैनिंग से लेकर दस्तावेज अपलोड तक हर स्टेप पर एप हैंग हो रहा है। सर्वर की बिगड़ी चाल ने पूरे दिन का काम अस्त-व्यस्त कर दिया है। एसडीएम बिल्हौर संजीव दीक्षित ने गुरुवार तक 50 फीसदी फीडिंग का टारगेट तय किया था। इसके लिए सुबह से ही तहसील सभागार में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया, लेकिन सर्वर की जिद ने अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों को बेहाल कर दिया। दर्जनों लोग फीडिंग में जुटे रहे, पर बीएलओ एप बार-बार क्रैश होने से काम बार-बार रुकता रहा।

कुछ बूथों पर काम की गति बेहद धीमी थी, ऐसे में एसडीएम ने तहसील कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर रफ्तार बढ़ाने का प्रयास किया। फिलहाल बीएलओ पहले फार्म कलेक्ट कर रहे हैं और जहां भी नेटवर्क की थोड़ी भी सुविधा मिल रही है, वहीं जाकर स्कैनिंग व अपलोडिंग कर रहे हैं। सर्वर डाउन की समस्या अब एसआईआर प्रक्रिया पर सबसे बड़ा ब्रेक बन गई है, जिससे तय समय में लक्ष्य पूरा करना चुनौती बनता जा रहा है।

सर्वर की बेवफाई से अफसरों की चिंता बढ़ी

बिल्हौर विधानसभा में कुल मतदाता 4,06,178 हैं। जबकि अब तक केवल कल देर रात तक की रिपोर्ट में 1,54,338 (38त्न) मतदाताओं की फीडिंग ही हो पाई है। और 2,51,840 यानी 58 फीसदी वोटरों की फीडिंग बाकी है। सर्वर की बेरूखी के चलते यह काम निर्धारित समय में पूरा हो पाएगा। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।

सर्वर की बेवफाई ने अफसरों को भी परेशान कर रखा है। वे भी चिंतित हैं कि सारा काम पूरा हो जाने के बावजूद यदि सर्वर दगा देता रहा गया तब क्या करेंगे?

अपना दल (एस) में अमित श्रीवास्तव बने जिला उपाध्यक्ष

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। जिले में संगठन को धार देने के लिए अपना दल (एस) ने नई टीम उतार दी है। पार्टी की ओर से जारी सूची में पार्टी के लिए समर्पित कस्बे के अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव को जिला उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्णय के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। दूसरे मनोनयन में बरौली निवासी लोकेश कटियार को जिला व्यापार प्रकोष्ठ का कप्तान, जबकि अर्जुन दिवाकर को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला कमांडर बनाया गया है।

संगठन की रीढ़ माने जाने वाले पद पर आशीष तिवारी को जिला महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। मनोनयन के दौरान जिला प्रभारी विपनेश कटियार ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अब संगठन को ज़मीन पर मजबूत करने की कवायद तेज करनी होगी। नई टीम के गठन के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी आगामी रणनीति को लेकर सक्रिय मोड में आ गई है।

सम्पादकीय

सरकारी प्रयासों व जागरूकता में लाएं तेजी

ब्राजील के बेलेम में संपन्न कॉप-30 सम्मेलन में जारी 'जलवायु जोखिम सूचकांक-2026' रिपोर्ट में उल्लेखित आंकड़े भारत से जुड़ी जलवायु संकट की भयावह तस्वीर दिखाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित पहले दस देशों में शामिल हैं। यह डराने वाली रिपोर्ट बताती है कि पिछले तीन दशक में भारत में आई जलवायु संकट से जुड़ी आपदाओं में करीब अस्सी हजार लोगों को मौत का ग्रास बनना पड़ा। इतना ही नहीं करीब 170 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी देश को उठाना पड़ा है। ये आंकड़े जलवायु संकट के देश पर पड़ने वाले घातक प्रभावों की तस्वीर उकेरते हैं। जो बताते हैं कि इस संकट से उबरने के प्रयासों में और तेजी लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस दिशा में यदि युद्ध स्तरीय प्रयास तेज नहीं किए जाते तो भविष्य में परिणाम और घातक हो सकते हैं। ये प्रयास केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी तेज करने की जरूरत है। जागरूकता अभियानों में भी तेजी लाने की जरूरत है। इस संकट ने फसलों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव से हमारी खाद्य श्रृंखला पर भी संकट मंडरा सकता है। हमें 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का पेट भरने के लिये इस दिशा में शोध-अनुसंधान के साथ व्यापक किसान जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है।

दरअसल, जलवायु संकट के चलते देश में जो ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके पीछे लगातार आ रहे चक्रवात, कुछ इलाकों में सूखे और बाढ़ की लगातार पैदा होती स्थितियां हैं। जाहिर इसके मूल में तेजी से बढ़ता वातावरण का तापमान ही है। जिसका मुख्य कारक ग्लोबल वार्मिंग ही है। निश्चित रूप से भारत में जलवायु संकट की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। जो जीविका संकट भी पैदा कर रहा है।

दरअसल, बेलेम में संपन्न कॉप-30 सम्मेलन में जारी की गई 'जलवायु जोखिम सूचकांक-2026' रिपोर्ट उन संकटपूर्ण स्थितियों का भी खुलासा करती है जो जलवायु संकट के कारण पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष भारी बारिश व विनाशक रूप में आई बाढ़ से देश में करीब अस्सी लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

इसमें दो राय नहीं कि भारत सरकार ने जलवायु संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष अपनी प्रतिबद्धता बार-बार जतायी है। इस संकट से उबरने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया है। देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

देश वनों का दायरा को भी बढ़ाने की जरूरत है। विकास देश की प्राथमिकता है, लेकिन यह विकास वनों के विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। साथ ही इस दिशा में जो भी कदम उठाये जाएं उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर कितना हो रहा है, इस बात का लगातार मूल्यांकन भी जरूरी है।

साथ ही रीति-नीतियों को प्रभावी तरीकों से अमलीजामा पहनाने की जरूरत होगी। जिसके लिये लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाइयों ग्राम पंचायत से लेकर शहरी निकायों को भी शामिल करने की जरूरत होगी।

जंक फूड को लेकर प्रभावी नीति की जरूरत

ज्योति मल्होत्रा

जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से जीवनशैली संबंधी रोग बढ़ने के सबूत सामने आ रहे हैं। जो चिंताजनक है। इसे रोकने को ठोस नीतिगत उपाय जरूरी हैं। लेकिन नीति नियंताओं का इस पर निर्णय लेने में रवैया टालमटोल वाला है।...जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से जीवनशैली संबंधी रोग बढ़ने के सबूत सामने आ रहे हैं। जो चिंताजनक है। इसे रोकने को ठोस नीतिगत उपाय जरूरी हैं। लेकिन नीति नियंताओं का इस पर निर्णय लेने में रवैया टालमटोल वाला है। दरअसल उद्योग जगत लॉबिंग, मार्केटिंग के जरिये इस संबंधी नियमन को कमजोर करता रहता है।

जानी-मानी मेडिकल पत्रिका, द लैंसेट ने इंसान के भोजन में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ), आमतौर पर जिसे जंक फ़ूड कहा जाता है, के बढ़ते इस्तेमाल पर शोधपत्रों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है। जिसमें बताया गया कि ये खाद्य पदार्थ कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर रहे हैं, दीर्घकालिक रोग पैदा कर रहे हैं, व सेहत असमानता बढ़ा रहे हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ कुछ हद तक प्रसंस्करण से गुज़रते हैं-गेहूं पीसकर आटा बनाना और चावल व दाल की मिलिंग कर उन्हें पकाने या सुरक्षित रखने लायक बनाना। समस्या पैदा होती है जब कृषि उत्पाद कारखानों में अत्यधिक प्रोसेस किये जाते हैं, उन्हें स्वस्थ, कुदरती बताकर पैक, ब्रांडेड व विपणन किया जाता है। भोजन को प्रसंस्कृत करने और सुरक्षित रखने के परंपरागत तरीके जैसे सुखाना, ठंडा करना, फ्रीज़ करना, पाश्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, बेकिंग और बॉटलिंग, खाने के कुदरती स्वरूप को काफी हद तक बनाए रखते हैं,"। दूसरी ओर, अल्ट्रा-प्रोसेसिंग भोजन पदार्थ के अवयवों में रासायनिक बदलाव कर देते हैं, उनमें एडिटिव्स मिलाकर रेडी-टू-कंज्यूम या लंबे समय बने रहने वाले उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के ऐसे उदाहरणों में मीठे ड्रिंक्स, पैकेज्ड स्नैक्स, पोटैटो चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, रीकॉन्सटिट्यूटेड मीट, कुछ ब्रेकफ़ास्ट सीरियल्स और फ़्लेवर्ड योगर्ट शामिल हैं।

ऐसे उत्पादों के ज़्यादा इस्तेमाल से ताज़ा या कम प्रोसेस्ड भोज्य पदार्थ खुराक से बाहर हो जाता है और मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य सेहत समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ये उत्पाद धरती की सेहत के लिए भी हानिकर हैं। इनके उत्पादन व परिवहन में बहुत ज़्यादा जैविक ईंधन खर्च होता है, और पैकेजिंग, जो ज़्यादातर प्लास्टिक की होती है, कचरा पैदा करती है।द लैंसेट श्रृंखला ने कई अध्ययनों के सबूतों का विश्लेषण किया है, जो दर्शाता है कि दुनिया भर में दीर्घकाल से प्रचलित भोजन करने के रिवायती ढंग की जगह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाना ले रहा है, और यह चलन तेज़ी से उन इलाकों में भी फैल रहा है जहां जंक फ़ूड अभी ज़्यादा नहीं था। दूसरा, सबूत पुख्ता करता है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाने के तौर-तरीके अपनाने से खुराक की गुणवत्ता काफी हद तक खराब हो जाती है। तीसरा, एकत्रित सबूत बताते हैं कि दीर्घकाल से कायम भोजन के ढंग की जगह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड द्वारा ले लेना, दुनिया में खुराक से जुड़े, कई दीर्घकालिक रोगों के बढ़ते बोझ का एक मुख्य कारक है। जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से जीवनशैली संबंधी रोगों की बढ़ती संख्या से जोड़ने वाले इतने सारे सबूत देखने के बावजूद, नीति नियंता और सरकारें निर्णय लेने में धीमी क्यों हैं? ऐसा इसलिए कि जंक फ़ूड इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि यह लॉबिंग, मार्केटिंग और जन संपर्क के ज़रिए नियम व नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करती रहती है। द लैंसेट श्रृंखला में दिखाया गया डेटा हैरानीजनक है। 2024 में, शीर्ष तीन फ़ूड कॉर्पोरेशन-कोका कोला, पेप्सिको और मोंडेलेज़-ने विज्ञापन पर कुल 13.2 बिलियन डॉलर खर्च किए ।

मौलिक कर्तव्यों के पालन से कर्मयोग की राह

नागरिक उदासीनता

ज्वाला सिंह दास

मौलिक कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण भारत में नागरिक उदासीनता बढ़ी है, जो स्वच्छता की कमी और सार्वजनिक संपत्ति की उपेक्षा जैसी समस्याओं में परिलक्षित होती है।आज़ादी ने हमें अधिकार दिए, मगर हमने कर्तव्य भुला दिए? यही असंतुलन आज भारत की सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है। सदियों की गुलामी के बाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ज़रूरी था। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि सिर्फ़ अधिकारों पर ज़ोर देने से एक स्वस्थ और सक्रिय समाज नहीं बन सकता। एक ऐसा राष्ट्र, जो केवल अपने अधिकारों की मांग करता हो, मगर अपने कर्तव्यों को भूल जाए, वह नागरिक उदासीनता और व्यवस्थागत विफलताओं का शिकार हो जाता है।

यह उदासीनता श्रीमद्भगवद्गीता के 'स्व-धर्म' सिद्धांत का उल्लंघन है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने पर ज़ोर देता है। जब नागरिक यह मान लेते हैं कि समस्याओं को नेता या अधिकारियों द्वारा हल किया जाएगा, तो वे पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे अपने मौलिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी से भागते हैं। मौलिक कर्तव्य इस पलायनवाद का मुकाबला करने और नागरिक को यह याद दिलाने के लिए एक कानूनी-नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं कि सामूहिक प्रगति उनकी आत्म-अनुशासित कार्रवाई पर निर्भर करती है।इसी असंतुलन को दूर करने के लिए, 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के माध्यम से संविधान में भाग चार-ए और अनुच्छेद 51ए को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में 86वें संशोधन (2002) में शिक्षा के अधिकार से जुड़ा एक और कर्तव्य (51ए(के)) जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य अक्सर सिर्फ़ 'नैतिक उपदेश' मानकर नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं क्योंकि इन्हें सीधे तौर पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यह नज़रिया अधूरा है। ये 11 मौलिक कर्तव्य वास्तव में भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए 'निष्काम कर्म' उपदेशों का ही रूप हैं। ये कर्तव्य हमें सिखाते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व ही हमारा 'धर्म' है। भगवद्गीता का 'निष्काम कर्म' (फल की इच्छा के बिना कर्तव्य करना) भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक आवश्यक मनोवैज्ञानिक इंजन प्रदान करता है। गीता का सूत्र-'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन-' सिखाता है कि उत्कृष्टता (अनुच्छेद 51(ए)(जे)) केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब नागरिक पुरस्कार या इनाम के लालच के बिना ये केवल कर्तव्य के लिए कार्य करते हैं।उत्कृष्टता 51(ए(जे))का कर्तव्य सीधे निष्काम कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है, जो फल की चिंता किए बिना अपने कार्य को कुशलता और समर्पण के साथ करने पर ज़ोर देता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा (51ए(आई)) गीता के अध्यात्म ज्ञान (पदार्थ की नश्वरता) से प्रेरित है। यह ज्ञान भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव और अहंकार को कम करता है, जिससे नागरिक सार्वजनिक संपत्तियों को 'मेरा' मानकर उनकी सुरक्षा का दायित्व लेते पर्यावरण की रक्षा (51ए(जी)) का उपदेश लोकमंगल का आधुनिक रूप है। यह सभी जीवों के प्रति एक नैतिक दायित्व को स्थापित करता है, जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना (51ए (एच)) आध्यात्मिक विवेक (तर्क और सही-गलत का भेदभाव) का धर्मनिरपेक्ष रूप है।असम के जादव पायेंग, जिन्हें 'फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है, निष्काम कर्म के माध्यम से संवैधानिक उद्देश्यों को ज़मीन पर उतारने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1979 में, बाढ़ के बाद सांपों को गर्मी से मरते हुए देखने के दुखद अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया।

चलती स्लीपर बस में भीषण आग, बची 43 यात्रियों की जान

रामादेवी फ्लाईओवर पर दौड़ती बस के ऊपर रखे सामान से उठी लपटें, मिनटों में पूरी बस बनी आग का गोला

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र के रामादेवी फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब वाराणसी की पलक ट्रेवेल्स की चलती स्लीपर बस के ऊपर रखे सामान में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस में करीब 43 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश सो रहे थे। लेकिन फ्लाईओवर पर ड्यूटी प्वॉइंट पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों की तत्परता ने सभी की जान बचा ली।

गुरुवार रात दिल्ली से वाराणसी के लिए निकली यह स्लीपर कोच बस जब रामादेवी फ्लाईओवर पर पहुंची, तभी संदिग्ध परिस्थितियों में बस की छत पर रखा सामान धधक उठा। आग देखते ही चालक रिषी यादव बस रोककर मौके से भाग निकला, जबकि पास के ट्रैफिक पिकेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौडक़र यात्रियों को एक-एक कर बस से बाहर खींचा। कुछ ही मिनट में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।फ्लाईओवर पर लगी आग के कारण दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचीं दमकल की आधा दर्जन गाडय़िाँ और चकेरी पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बस के साथ यात्रियों का लाखों का सामान, कपड़े, जरूरी दस्तावेज और नकदी जलकर राख हो गई।जाजमऊ फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री की जान नहीं गई। पुलिस ने बस को हटवाकर फ्लाईओवर पर यातायात बहाल कराया।

लग गया भीषण जाम

बस में आग लगने के बाद फ्लाईओवर पर भीषण जाम लग गया। करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। मौके पर जब आग बुझाई गई उसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। करीब दो घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका।

घाटमपुर में लेबर मंडी को स्थाई स्थान देने की उठी मांग

हर बाजार को मिल रही सुविधा, मजदूरों की मंडी अब भी उपेक्षित

» प्रमुख संवाददाता /स्वराज इंडिया

कानपुर। घाटमपुर में लेबर मंडी को स्थाई स्थान देने की मांग ने एक बड़ी और लंबे समय से उपेक्षित समस्या की ओर ध्यान खींचा है। एक गेस्ट हाउस संचालक चंद्रवीर सिंह ने इस संबंध में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। क्षेत्रीय लोगों का भी यह कहना है कि मजदूर वर्ग अपने दैनिक रोजगार की तलाश में मजबूरीवश सडक़ किनारे खड़ा होता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि इन असंगठित मंडियों के कारण सुबह के पीक टाइम में यातायात बाधित हो जाता है। काम पर निकलने वाले लोग जाम में फंसकर देर से पहुँचते हैं, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक वाहनों के आवागमन में भी बाधा आती है।

यह समस्या हर दिन दोहराई जाती है, परंतु समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाए जा रहे। चंद्रवीर सिंह सिंह समेत क्षेत्रीय निवासियों व दुकानदारों ने मांग की है कि लेबर मंडियों को एक स्थाई और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जाए, जहां मजदूरों को मौसम से बचाव के लिए टीन शेड, पानी, बैठने की जगह और सर्दियों में अलाव जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। जब मंडी एक तय स्थान पर चलेगी, तो शहर के मुख्य मार्गों पर लगने वाले रोज़मर्रा के जाम से भी जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार जहां फल-सब्जी मंडियों और बाजारों को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है, वहीं मजदूरों की यह अनौपचारिक परंतु सबसे ज़रूरी मंडी अभी भी व्यवस्था से दूर है।

अखिलेश दुबे को 37 शिकायतों में क्लीनचिट, छह की चल रही जांच

एसआईटी की जांच में नहीं मिले साक्ष्य

»वरिष्ठ संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। भाजपा नेता रवि सतीजा को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल गए अधिवक्ता अखिलेश दुबे को बड़ी राहत मिली है। उसके खिलाफ आईं 43 शिकायतों में से 37 में एसआईटी ने क्लीनचिट दे दी है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने छह मामलों में डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी सबूत एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं।

छह अगस्त 2025 को भाजपा नेता रवि सतीजा ने बर्रा थाने में अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा, टोनू यादव, विमल यादव, अभिषेक बाजपेई समेत अन्य पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद अखिलेश दुबे और उसके साथियों पर दो किदवईनगर, कोतवाली में अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई, जबकि जूही क्षेत्र के 15 साल पुराने मामले में फिर से जांच शुरू हो गई। यह कार्रवाई एसआईटी की जांच के बाद हुई थी। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने सितंबर में ऑपरेशन महाकाल लॉन्च कर दिया। इसमें अखिलेश दुबे के अलावा कई जमीनों पर कब्जा करने और अन्य अपराधियों के खिलाफ शिकायतें आईं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से एसआईटी को बारीबारी से जांच दी गई। अखिलेश दुबे और उसके साथियों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।

इस बीच शिकायत करने वालों ने अखिलेश दुबे मुक्ति मोर्चा बनाया और पुलिस अधिकारियों को जांच में सहयोग करने की बात कही। नवंबर में अखिल कुमार को डिजिटल इंडिया का सीईओ बनाकर भेज दिया, जबकि एडीजी रघुबीर लाल को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। उनके आने पर एसआईटी की जांच को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं। हालांकि पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने पहले ही दिन आकर एसआईटी के अधिकारियों से बातचीत की थी। उनसे जांच के संबंध में जानकारी की थी। उन्होंने एसआईटी के अधिकारियों को बेहतर जांच के निर्देश दिए थे। बीच बीच में समीक्षा भी हुई। एसआईटी ने गुरुवार को जांच पूरी कर ली है। इसमें 43 शिकायतों में से 37 में क्लीनचिट मिल गई हैं। उनमें पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, जबकि वक्फ से संबंधित चार मामलों की जांच जिला प्रशासन कर रहा है। करीब 10 के आसपास मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। छह शिकायतों की जांच चल रही है। दो शिकायतकर्ता ऐसे भी मिले हैं,

इन शिकायतों में नहीं मिले साक्ष्य

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के मुताबिक, अखिलेश दुबे के खिलाफ अधिकतर दी गई शिकायतें जमीन से संबंधित मामलों में थी। इनमें शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य नहीं दिए गए।

- अखिलेश दुबे के खिलाफ केडीए की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाकर शिकायत हुई।
- वादी की संपत्ति को अखिलेश दुबे की संपत्ति बता दिया गया। यह बात एक समाचार पत्र में छपी थी।
- अखिलेश दुबे ने एक कमरा लिया था जहां आरोप लगाने वाली लड़कियां रहती थीं। जांच में कमरा सिपाही का निकला।
- गोविंदनगर और सिविल लाइंस में किरायेदारी के विवाद में अखिलेश दुबे पर धमकी देने की शिकायत की गई थी।
- पति को बंधक बनाकर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप।
- बिधनू में एयरफोर्स कर्मी की पत्नी ने अखिलेश दुबे की साथी महिला पर पति पर झूठी एफआईआर कराने का आरोप लगाया था।
- भाई और पिता के बीच के विवाद में अखिलेश दुबे का नाम ले लिया गया।
- अखिलेश दुबे के साथ मिलीभगत कर बेटे पर झूठी एफआईआर कराने का आरोप।
- बिधनू की 36 बीघे से अधिक जमीन पर अखिलेश दुबे ने कब्जा कर लिया।
- केडीए की कार्रवाई के दौरान अखिलेश दुबे के साथियों ने मारपीट की थी।
- अखिलेश दुबे ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करा दी।

अखिलेश दुबे के खिलाफ आई 37 शिकायतों में कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है। छह मामलों में एसआईटी को डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान, सीडीआर और अन्य सबूत एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रघुबीर लाल, पुलिस कमिश्नर कानपुर

जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पुलिस स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसकी जांच सर्वमान्य है। सीएम योगी की सरकार में अन्याय नहीं हो सकता है। पुलिस कमिश्नर जो भी करेंगे वह जनहित में ही होगा।

रवि सतीजा,भाजपा नेता

अखिलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाले शैलेंद्र पर पुलिस ने तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर ली जबकि अखिलेश के परिवार ने मेरे खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की हैं। उसकी शिकायत डीसीपी साउथ से करने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है।

पीड़िता, होटल कारोबारी

इन मामलों में होगी जांच

- गोविंदनगर के तत्कालीन इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के खिलाफ युवती के कोर्ट में दिए गए बयान के विपरीत चार्जशीट दाखिल करने का आरोप। इस मामले में अखिलेश के दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप भी लगा है।
- अधिवक्ता की ओर से अखिलेश दुबे के साथी टोनू यादव पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी देने का आरोप है।
- गोविंदनगर के कारोबारी की ओर से 2015 में धमकाने और बेइज्जती करने की शिकायत दी गई है।
- जयकांत बाजपेई के भाई रजयकांत बाजपेई के साथ अखिलेश दुबे के साजिश रचने का आरोप।
- गोविंदनगर की एक दुकान पर अखिलेश दुबे द्वारा कब्जा करने का आरोप।
- केडीए वीसी के पीए कश्यपकांत दुबे और अखिलेश दुबे के बीच सांठगांठ होने की शिकायत।
- निरालानगर में कर्मचारी नेता भूपेश अवस्थी के खिलाफ सरकारी जमीन को प्लॉट बताकर बेचने की शिकायत।
- श्यामनगर के पूर्व पार्षद की ओर से फर्जी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने और धमकी देने का आरोप।

गंभीर रूप से घायल किशोर की मदद को आगे आई महापौर प्रमिला पाण्डेय

»वरिष्ठ संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।जनता दर्शन के दौरान आज एक दर्दनाक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई, जब ग्वालटोली की एक पीड़ित माँ रोते हुए महापौर प्रमिला पाण्डेय के पास पहुँची। महिला ने बताया कि उसका पुत्र कृष्णा दिनांक 26.11.2025 को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका इलाज तिलक नगर के कनिष्क हॉस्पिटल में चल रहा है। इलाज में अब तक लगभग 50 हज़ार रुपये खर्च हो चुके थे, पर आगे का खर्च उठाना परिवार के लिए असंभव हो गया था।

महापौर प्रमिला पाण्डेय ने गरीब परिवार की दशा देख तुरंत मानवीय संवेदना दिखाते हुए स्वयं कनिष्क हॉस्पिटल पहुँचकर अस्पताल प्रशासन से वार्ता की। महापौर ने अपने प्रयासों से इलाज के खर्च में 40 हज़ार रुपये की बड़ी छूट दिलवाई और किशोर को डिस्चार्ज कराकर तुरंत हैलट अस्पताल ले गईं।हैलट पहुँचकर उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी चिकित्सालय के प्राचार्य डॉ. संजय काला से मुलाकात की और घायल किशोर के लिए सर्वोत्तम एवं नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्राचार्य डॉ. संजय काला ने आश्वस्त किया कि मरीज को पूरी सुविधा और बेहतर उपचार दिया जाएगा तथा जल्द ही वह स्वस्थ होगा।

महापौर का यह प्रयास एक बार फिर बता गया कि जरूरतमंद की मदद में आगे आना ही जनसेवा का वास्तविक स्वरूप है।

ट्रैक्टर की टक्कर से बच्चे की मौत, मचा कोहराम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। खेतों पर काम कर रहे माता पिता को खाना देने जा रहे मासूम बच्चे को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत औरंगपुर गहदेवा निवासी प्रेम शंकर कठेरिया का पुत्र किशन उम्र लगभग 8 वर्ष सुबह अपने माता-पिता जो की खेतों पर काम कर रहे थे वहीं जा रहा था। तभी मिट्टी डाल रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। घटना की जानकारी होते ही परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ककवन ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। माता आशा देवी,बहन प्रियंका, निशा,भाई सुमित व अमित का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी होते ही ग्राम प्रधान बलवान सिंह यादव व रोजगार सेवक सत्येंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने परकार्रवाई की जाएगी।

अज्ञान वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव के समीप स्कूटी सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। जानकारी के अनुसार भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के चांदापुर गांव निवासी ताहिर पुत्र मुकीम (40) स्कूटी से कालपी की ओर से भोगनीपुर की ओर आ रहा था। ताहिर अभी कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव के समीप पहुंचा ही था कि तभी उसकी स्कूटी में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगो के द्वारा कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा।

जैनपुर की फैक्ट्रियों का धुआं आबोहवा में घोल रहा जहर

» किसानों की पराली पर कार्रवाई, लेकिन धुआं उगलती फैक्ट्रियों पर प्रदूषण विभाग खामोश

» जहर और बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ा, जिम्मेदार अधिकारी बोले उन्हें जानकारी नहीं

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। जैनपुर औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों व ईंट भट्ठों से निकलने वाला जहरीला धुआं आबोहवा में जहर घोल रहा है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। कई फैक्ट्रियों में मानक ऊंचाई की चिमनियां नहीं हैं। इनसे निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। जहर उगला रही इन इकाइयों पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया है। बढ़ता प्रदूषण सांस की परेशानी की प्रमुख वजह बना है।

प्रदूषण फैला रहे उद्योगों की अनदेखी व संसाधनों की कमी बता जिम्मेदारों के पल्ला झाड़ने से आसमान में बढ़ रही परत बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। शहर के कई इलाकों में कूड़ा जलाने से लेकर चिमनियों से उठता काला धुआं वायु प्रदूषण को गंभीर स्तर पर पहुंचा रहा है, जिससे धुंध की परत लगातार मोटी होती जा रही है। प्रशासन किसानों की पराली पर कार्रवाई तो सख्ती से कर रहा है, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को लेकर विभाग की लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा बन रही है।जिले के जैनपुर, हिम्मापुरवा, मोहाना, पतरा, पृथ्वीपुरवा, तिलौची और जुनिया समेत कई गांवों में फैक्ट्रियों से उठता जहरीला धुआं लोगों में फेफड़ों, एलर्जी, लीवर और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बढ़ा रहा है। जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में ये फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से लगातार धुआं उगल रही हैं। इससे आसपास की आबादी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे से घिरी है।रनियाङ्ककरबे में प्रदूषण नियंत्रण विभाग का कार्यालय होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। विभाग केवल मौके-मौके पर छोटी जांच और एनओसी जारी करने तक ही सीमित है, जबकि जिले में न तो प्रदूषण की नियमित जांच की व्यवस्था है और न ही इसके लिए आवश्यक संसाधन। ऐसे में धुएं के रूप में हर रोज घुलता जहर नागरिकों की सांसें और जिंदगी लगातार कम कर रहा है।

क्या बोले जिम्मेदार अधिकारी

प्रदूषण अधिकारी मनोज चौरसिया का कहना है कि जानकारी नहीं है। दिखवाया का जा रहा है निश्चित ही कार्यवाही की जायेगी। लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

भीषण हादसा

खनिज लदा था डंपर, परिवार पर कहर बनकर बरसी मौत

बच्ची समेत सात की मौके पर ही मौत, कार हुई चकनाचूर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

सहारनपुर जनपद के सैय्यद माजरा का परिवार किसी काम से बाहर निकला था लेकिन शहर पार भी नहीं हुआ कि खनिज से भरा डंपर काल बनकर बरस पड़ा। एक ही झटके में सात जिंदगियां खत्म हो गईं। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर के सैय्यद माजरा गांव का रहने वाला एक परिवार कार से कहीं जा रहा था।

जैसे ही कार गांव की सीमा पार करके एक्सप्रेसवे पर पहुंची, उसी समय देहरादून की दिशा से तेज रफ्तार में खनिज से भरा एक डंपर आ रहा था। जो अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार को अचानक सामने देखकर डंपर चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया। नियंत्रण खोने पर डंपर सीधे कार के ऊपर पलट गया।

हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह डंपर के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, कार में मौजूद सात लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कड़ी मशक्कत के बाद निकलवाया। जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहन को डंपर के नीचे से निकलवाया गया।

इनकी हुई मौत

संदीप(35) पुत्र महेंद्र
रानी पत्नी महेंद्र
रानी की बेटी
एक अज्ञात उम्र 45
विपिन, संदीप की मौसी का लड़का दौलतपुर, चिलकाना
उमेश सिंह 52 (मेहदुदपुर रावली हरिद्वार)
समधी महेन्द्र सिंह का

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। कार में सवार परिवार कहां जा रहा था। इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात रोककर बचाव कार्य चलाया गया। फिलहाल पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और हादसे की जांच जारी है। वहीं मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जाम लगा दिया।

जीएसटी-एमनेस्टी बढ़ाने की मांग तेज, व्यापारियों ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

» कोविड काल के दो सबसे कठिन वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 को भी एमनेस्टी स्कीम में शामिल करने का अनुरोध

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। कोविड काल की आर्थिक तबाही झेल चुके व्यापारियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 को भी जीएसटी-एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत शामिल करने की मांग उठाई है। आर्थिक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी (कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र) के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरन जीत सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य कर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2020-21 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और 2021-22 में कोविड की दूसरी घातक लहर ने व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को भी मोरेटोरियम, एनपीए रोक और रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क लागू करना पड़ा इससे स्पष्ट है कि व्यापारी अभूतपूर्व संकट में थे।व्यापारियों का कहना है कि ऐसे समय में जीएसटी रिटर्न व कंप्लायंस पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए इन दो वर्षों को भी एमनेस्टी स्कीम का लाभ मिलना अत्यंत आवश्यक है।

जीएसटी अपील में 'रिमांड' अधिकार और छोटे वैट बकाये समाप्त करने की भी मांग

ज्ञापन में जीएसटी प्रणाली से संबंधित दो अन्य महत्वपूर्ण सुधारों की भी मांग की गई। पहला जीएसटी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 'रिमांड' की शक्ति प्रदान की जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कई मामलों में अधिकारी दस्तावेज ठीक से नहीं देखते और आदेश पारित कर देते हैं।

अपीलीय अधिकारी के पास मामले को पुनः जांच के लिए भेजने (रिमांड) का अधिकार न होने से छोटे-छोटे विवाद भी ट्रिब्यूनल व अदालतों तक पहुँच जाते हैं। रिमांड की शक्ति मिलने से न्याय निचले स्तर पर ही सुनिश्चित हो सकेगा।

दूसरा वैट युग के 2000 रुपये तक के छोटे बकाये स्वतः समाप्त किए जाएं। प्रतिनिधियों के अनुसार, इन छोटे बकायों में अधिकांश विलंब शुल्क है, जिसकी वसूली पर प्रशासनिक खर्च वसूल की जाने वाली राशि से अधिक हो जाता है।

इसलिए ऐसे बकाये विभाग और व्यापारी दोनों के हित में समाप्त कर दिए जाने चाहिए।ज्ञापन सौंपने वालों में एडवोकेट पुष्कल त्रिपाठी, एडवोकेट प्रांजल त्रिपाठी, सी.ए. अमन कौर सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे।

दो घंटे में अलग-अलग रिपोर्ट रिकाबगंज की डॉ. लाल पैथ लैब सील

स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

- बिना रजिस्ट्रेशन डॉक्टर, फर्जी तकनीशियन लैब में जांच करते पाए गए
- मरीज की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की जांच में खुला बड़ा खेल

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के रिकाबगंज में स्थित डॉ. लाल पैथ लैब की मुख्य शाखा गुरुवार को उस समय सुर्खियों में आ गई, जब स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने इसे सील कर दिया। यह कार्रवाई एक मरीज की शिकायत पर शुरू हुई, जिसने मधुमेह की जांच में दो घंटे के अंतराल में आई दो अलग-अलग रिपोर्ट का मामला उठाया था। रिपोर्टों में इतना बड़ा अंतर मिला कि पूरा संदेह सीधे लैब की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर आ गया।

स्वास्थ्य विभाग की टीम जब रिकाबगंज स्थित लैब में पहुँची तो वहां जो स्थिति सामने आई, उसने विभाग को चौंका दिया। लैब में कुल पांच तकनीशियन कार्यरत पाए गए, लेकिन केवल एक के पास अधिकृत पंजीकरण (इम्पैनलमेंट) प्रमाण पत्र था।

बाकी चार बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के गंभीर चिकित्सा जांच करते पाए गए। निरीक्षण में एक महिला डॉक्टर भी मौजूद थीं, जो बिना आधिकारिक मेडिकल रजिस्ट्रेशन के पैथोलॉजिकल गतिविधियों में संलग्न थीं। यह स्वास्थ्य नियमों का सीधा उल्लंघन है। यहां तक कि प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी से किया गया अनुबंध भी संदिग्ध पाया गया।

एसपी ग्रामीण अयोध्या बलवंत चौधरी

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बनियान ने पुष्टि की है कि इस लैब के एक अन्य सेंटर पर पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की मंडलीय बैठक में शहर की अन्य निजी प्रयोगशालाओं की व्यापक जांच की रणनीति तय की जाएगी। जिला प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए हस्तक्षेप किया है। डॉ. हरिओम गुप्ता ने आदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी स्थिति में लैब का सील न खोला जाए। डॉ. लाल पैथ लैब जैसी प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम का इस्तेमाल कर इस तरह की अनियमितताएं मिलने से मरीजों की सुरक्षा, जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता और निजी लैबों की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह कार्रवाई सिर्फ एक लैब तक सीमित नहीं है यह सिस्टम में छिपे बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है, जो बिना योग्य स्टाफ, बिना लाइसेंस और बिना सुरक्षा मानकों के मरीजों के जीवन से सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की आक्रामक कार्रवाई के बाद अब यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि अयोध्या की और कौन–कौन सी लैबें इसी तरह नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। आज होने वाली मंडलीय बैठक के बाद कई और सेंटरों पर शिकंजा कसने की पूरी संभावना है।

एसपी देहात ने की शिकायत

अयोध्या के एसपी देहात बलवंत चौधरी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को एचबीए 1 सी टेस्ट कराने के लिए रिकाबगंज स्थित लाल पैथोलॉजी के कलेक्शन ब्वॉय अमित पाठक को सैंपल दिया था। पहली भेजी गई रिपोर्ट में लैब नंबर 499853202 और प्रोस्टेट अयोध्या लैब, रिकाबगंज, फैजाबाद अंकित था, जिसमें उनका एचबीए 1 सी 10.2 दर्शाया गया जो बेहद गंभीर स्तर होता है।

चिकित्सक से संपर्क करने पर डॉक्टर ने इस रिपोर्ट को संदिग्ध बताते हुए दोबारा जांच कराने की सलाह दी। इस पर अमित पाठक ने स्वीकार किया कि टेस्ट गलत हुआ था और दूसरी रिपोर्ट भेजी, जिसमें एचबीए 1 सी 6.5 दर्ज था। अगले ही दिन एसपी देहात ने अयोध्या की एक अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में जांच कराई, जहां एचबीए 1 सी 6.2 पाया गया। पहली रिपोर्ट में (10.2) जैसे खतरनाक परिणाम सामने आने पर एसपी देहात ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे प्रकरण की शिकायत सीएमओ को सौंप दी।

इटावा में महिला अपराधों पर पुलिस का कड़ा एक्शन जारी

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इटावा। कानपुर परिक्षेत्र में तैनात तेजतर्रार एडीजी आलोक सिंह के सख्त निर्देशन तथा एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में चलाए जा रहे आपरेशन कन्विक्शन ने बड़ा प्रभाव दिखाया है। जिले की पुलिस ने अदालत में लंबित मुकदमों की तेज और प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।थाना चौबिया क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के एक महत्वपूर्ण मुकदमे में पुलिस और अभियोजन की संयुक्त सक्रियता ने निर्णायक भूमिका निभाई।

मजबूत साक्ष्यों और दृढ़ पैरवी से प्रभावित होकर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल सत्तर हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय का यह परिणाम जिले में महिला अपराधों को लेकर अपनाई जा रही कड़ी नीति का स्पष्ट उदाहरण है। अभियान के तहत लगातार हो रही प्रभावी पैरवी से विभिन्न प्रकरणों में अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

आरटीआई में 'सूची गायब', स्वच्छता रैंकिंग में देश में 28वाँ स्थान!

» आरटीआई ने खोला नगर निगम का खेल, निरीक्षण 'कागज़ों में', जिम्मेदार 'गायब'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। देश भर में स्वच्छता रैंकिंग में 28वां स्थान हासिल करने वाली अयोध्या की सफाई व्यवस्था अब गंभीर सवालों में घिर चुकी है। वह भी इसलिए क्योंकि जब वास्तविक निरीक्षणों का रिकॉर्ड ही मौजूद न हो, तो रैंकिंग कितनी विश्वसनीय है यह सवाल हर जागरूक नागरिक पूछने लगा है। सिविल लाइन रोडवेज से चौक तक स्थित मॉल, कॉम्प्लेक्स, निजी दुकानों में शौचालय, यूरिनल, निरीक्षण, नोटिस और चालान से जुड़ी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सावंत ने आरटीआई के जरिए मांगी। और जवाब मिला सूची उपलब्ध नहीं है। यही चार शब्द अयोध्या नगर निगम की संपूर्ण स्वच्छता व्यवस्था का 'चरित्र प्रमाण पत्र' बन गए हैं।

जब रिकॉर्ड ही नहीं, तो निरीक्षण कैसे? और जब निरीक्षण नहीं, तो 28वीं रैंक किस आधार पर? स्थानीय नागरिकों का यही प्रश्न अब नगर निगम को घेरे हुए है। महिला नागरिक रीना (काल्पनिक नाम) की पीड़ा महिलाओं के लिए शौचालय ढूँढना यहाँ रोज़ की चुनौती है। जरूरत के समय सुविधा कहीं नहीं मिलती। जब सूची ही नहीं है, तो किस आधार पर दावा करते हैं कि सब ठीक है? रीना की बात अयोध्या की उन सैकड़ों महिलाओं की आवाज़ है जिनके लिए सार्वजनिक शौचालय एक 'भाग्य' जैसा लगता है। सिविल लाइन के एक दुकानदार ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा तीन साल में कभी किसी अधिकारी को निरीक्षण करते नहीं देखा। सफाई व्यवस्था कागज़ों में चलती है। सूची नहीं है मतलब निरीक्षण हुए ही नहीं। अगर यह बयान सच है, तो नगर निगम की कार्यप्रणाली सिर्फ ढकोसला ही नहीं, बल्कि यह करोड़ों की सफाई व्यवस्था पर बड़ा सवाल है।

अयोध्या नगर निगम की सफाई व्यवस्था का सच

आरटीआई लगाने वाले अभिषेक सावंत

सेवा में, जन सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अयोध्या, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। विषय- व्यावसायिकप्रतिष्ठानों के निरीक्षण और कार्रवाई-सूचना का अनुरोध आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आदरणीय महोदय, निवेदन है कि मैंअयोध्या जनपद का एक जागरूक नागरिक होने के नाते सिविल लाइन -Roadways से चौक — दोनों तरफ- पर स्थित निजी व्यावसायिकप्रतिष्ठानों-मॉल-शॉप-कम्प्लेक्स में पुरुष-महिला मूत्रालय-शौचालय -toilet-urinal- की उपलब्धता, निरीक्षण, अनुपालनोंऔर नगर निगम की कार्यवाही से सम्बंधित जानकारी -सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6-1-के अंतर्गत प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया प्रत्येक प्रश्न के लिएप्रमाणित -certified- प्रतियाँ और जहाँ उपलब्ध हो इलेक्ट्रॉनिक-soft copy - PDF- भी प्रदान करें। · क्षेत्र- सिविललाइन — Roadways से चौक -दोनों तरफ — जो भी व्यावसायिकदुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल औरमल्टी-शॉप प्रतिष्ठान सड़क के दोनों ओर आते हों। -यदि विभाग क्षेत्र-सीमा अलगपरिभाषित करता है तो कृपया उसकी स्पष्ट मानचित्र-वार्ड-सी.सर्कल पहचान सहित बताएंऔर उसका स्कैन करें।· अवधि-गत 3 वर्ष — 1 जनवरी 2022 से 13 सितंबर 2025 तक -दोनों तिथियाँसम्मिलित। अत आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे निम्नलिखित बिंदुओं परजानकारी प्रदान करने की कृपा करें 1- नगरनिगम-स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में शौचालय-स्वच्छतासंबंधी कितने निरीक्षण किए गए,उनकी तिथि सहित सूची उपलब्ध कराएं।2- निरीक्षणरिपोर्ट-मिनट्स-साइट नोटिंग की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।3- इसअवधि में कितने प्रतिष्ठानों को नोटिस-शो कॉज़ नोटिस-चेतावनीजारी की गई, उनकी प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।4- इसअवधि में कितने प्रतिष्ठानों पर जुर्माना-कार्रवाई कीगई, उसकीप्रतियाँ -आदेश-रसीद- उपलब्ध कराएं। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त जानकारी पारदर्शिता एवं सार्वजनिक कल्याण कीभावना से शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।यदि मांगी गई कोई सूचना आपकेविभागाधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो, तो कृपया अधिनियम की धारा 6-3- के अंतर्गत संबंधित विभाग-अधिकारीको हस्तांतरित करें एवं मुझे सूचित क । यदिकिसी सूचना का अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो कृपया स्पष्ट लिखित रूप में बताया जाए किवह रिकॉर्ड क्यों उपलब्ध नहीं है और किस आदेश-नियमके तहत रखा नहीं जाता। आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। सादर अभिषेक सावंतसामाजिक कार्यकर्ता संपर्क – 8299021827दिनांक- 14-09- 2025

'सूची गायब होना अपराध'

आरटीआई लगाने वाले अभिषेक सावंत साफ कहते हैं सूची उपलब्ध नहीं है यह वाक्य किसी भी जिम्मेदार नगर निगम की सबसे बड़ी विफलता है। अगर रिकॉर्ड तीन वर्षों से तैयार ही नहीं हुआ, तो स्वच्छता रैंकिंग भी संदेहास्पद है। मैं यह मामला राज्य सूचना आयोग में ले जाऊंगा। यह बयान साफ बताता है कि मामला अब सिर्फ प्रश्न नहीं, बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप लेने जा रहा है। अयोध्या के नागरिक अब जवाब और कार्रवाई चाहते हैं उनकी मांग है कि सिविल लाइन, रोडवेज चौक क्षेत्र की सफाई व शौचालय निरीक्षण की पूरी सूची तत्काल जारी हो। तीन वर्षों में कितने नोटिस, चालान और जुर्माने हुए यह बताया जाए। महिला शौचालयों की भारी कमी दूर करने के लिए त्वरित कार्ययोजना लाई जाए। रिकॉर्ड गायब होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो। आस्था और पर्यटन की वैश्विक नगरी अयोध्या में स्वच्छता व्यवस्था का यह हाल निरीक्षण कभी हुए ही नहीं, सूची कभी बनी ही नहीं,और रैंक ऐसे मिल गई जैसे सब कुछ चमक रहा हो।आरटीआई ने सिर्फ दस्तावेज़ नहीं मांगे,आरटीआई ने सिस्टम की सच्चाई उघाड़ दी।अब गेंद नगर निगम के पाले में है या तो वे रिकॉर्ड पेश करें।यह सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं यह पारदर्शिता, ईमानदारी और प्रशासनिक जवाबदेही का मामला है।

जो दुनिया से चला गया उसकी फाइलें अब भी जिंदा!

9 साल बाद भी पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह की याचिकाओं से दो विभागों में हड़कंप

» 2009 की सडक़, नाली निर्माण याचिकाएं आज तक नहीं की गई निस्तारित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। सरकारी विभागों की एक अनोखी विडंबनाज्एक ऐसा सिस्टम जहां नेता मर जाते हैं, पर फाइलें नहीं! एक ऐसा तंत्र जहां याचिका की आत्मा 9-9 साल बाद भी दफ्तरों में भटकती रहती है। पूर्व सिंचाई मंत्री मुन्ना सिंह चौहान का निधन 30 जुलाई 2016 को हो चुका, लेकिन उनकी 2009 की दो याचिकाएँ लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को आज भी परेशान कर रही हैं।

स्वराज इंडिया इन्वेस्टिगेटिव

याचिका समिति की सर्किट हाउस में हुई बैठक में यह पूरा 'फाइल-भूचाल' सामने आया।दोनों याचिकाएँ सोहावल ब्लॉक में शारदा सहायक नहर की पटरी, सडक़ और नाली निर्माण से संबंधित थीं।

आरटीआई लगाने वाले अभिषेक सावंत

अधिकारियों ने स्वीकार भी किया निस्तारण अभी भी लंबित है। अब समिति तय करेगी कि इन 'भटकी हुई फाइलों' का अंत कैसे होगा।

एमएलसी के रूप में जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने वाले मुन्ना सिंह के परिवार में पहले पत्नी शोभा सिंह विधायक, अब पुत्र डॉ. अमित सिंह चौहान विधायक हैं। पर सबसे कड़वा सच यह है कि मुन्ना सिंह के न रहने के बाद भी उनकी याचिकाएँ अफसरों का पीछा नहीं छोड़ रहीं। यह सवाल अब बड़ा हो चुका है।

सर्किट हाउस में हुई बैठक में सभापति अशोक अग्रवाल और सदस्यों अनूप गुप्त, अरुण कुमार पाठक, मुकुल यादव, उमेश द्विवेदी, अनुसचिव रमेंद्र भाई पटेल, समीक्षा अधिकारी सौरभ सिंह, जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे, सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सबने जवाब दिए, पर असल जवाबदारी अभी भी हवा में ही तैरती दिखी।

अयोध्या में सडक़ और नाली निर्माण जैसी बुनियादी जरूरतों पर आधारित याचिकाएँ 16 वर्षों तक अगर अधूरी रहें, और नेता के निधन के नौ साल बाद भी दफ्तरों में भटकती रहें,

तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं यह प्रशासनिक अपराध है। सवाल साफ है इन 'प्रेत-फाइलों' का अंतिम संस्कार कब होगा?और इससे भी बड़ा सवाल अयोध्या के विकास की राह में आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति अटकाव बनकर बैठी है? यह स्टोरी इसी 'सिस्टम के भूत' को बेनकाब करती है।

अन्य नेताओं की फाइलें भी धूल खा रही

1. हीरालाल यादव (पूर्व एमएलसी) की नगर निगम के उसरू में 2021 की सीसी रोड व नाली निर्माण याचिका
2. लीलावती कुशवाहा (पूर्व एमएलसी) की फाइलें अब तक निस्तारित नहीं।
3. ध्रुव कुमार त्रिपाठी (एमएलसी) 2013 की एक याचिका अब भी अधूरी।
4. लाल बिहारी यादव (एमएलसी) 2022 की सडक़ङ्कनाली निर्माण याचिका अभी भी लंबित।

मौजूदा दौर में वसुधैव कुटुंबकम का विचार और अधिक प्रासंगिक

ध्यान योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया विश्व एकता और शांति पर जोर

कहा- तकनीकी के साथ समाज में बढ़ी ईर्ष्या और दुख; मेडिटेशन बचने का कारगर उपाय

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में शुक्रवार को ब्रह्मकुमारीज संस्थान की ओर से राज्यस्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं हैं। उनके साथ सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। मंच पर सीएम और राज्यपाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बिना पास और जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है और आज जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है तो यह (वसुधैव कुटुंबकम) विचार और अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने देश में आए बदलावों और नयी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है और आगे बढ़ने के अवसर हैं लेकिन समाज में उन्नति के साथ-साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन बढ़ रहा है।

राष्ट्रपति ने सुझाव देते हुए कहा, आज आवश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने की ही नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा भी शुरू करें। इसका कदम ब्रह्माकुमारीज ने उठाया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। मुर्मू ने मानव स्वभाव की विवेचना करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि दूसरे पर विश्वास करें, लेकिन विश्वास वहीं टिकता है जहां मन शांत हो, विचार स्वच्छ हों और भावनाएं शुद्ध हों। उन्होंने कहा, जब हम कुछ क्षण रुक कर स्वयं से संवाद करते हैं तो इस बात का अनुभव होता है कि शांति और आनन्द किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर जब आत्मिक चेतना जागृत होती है तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाता है।

शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है

राष्ट्रपति ने कहा, शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है तथा वहीं से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है। सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की आधारशिला रही है। राष्ट्रपति ने ब्रह्माकुमारी को सजे हुए कलश और ब्रह्माकुमारों को झंडे प्रदान किये, जिनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में जाएगी। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्था ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर करने की दिशा में कदम उठाया और यह वैश्विक चेतना का आरंभ था। यह आध्यात्मिक वटवृक्ष 136 देशों में अपनी सुगंध बिखेर रहा है और इसकी शाखाएं दिलों को जोड़ रही है। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है जब विश्व एकता जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं।

योगी ने कहा, एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति का जीवन एक शिक्षक के रूप में प्रेरणादायी रहा है और इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक उनकी जीवन यात्रा हर भारतीय के लिए एक उदाहरण है। इसके पहले उप्र की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमौसी हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया।

मुजफ्फरनगर के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरी

» लखनऊ, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने उन्नीसवीं नेशनल जम्बूरी में प्रतिभाग करने पहुंचे मुजफ्फरनगर जिले के स्काउट्स एवं गाइड्स दल का शुक्रवार को लखनऊ स्थित आवास पर आत्मीय स्वागत किया। मंत्री ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि ये बच्चे मुजफ्फरनगर के हैं, और इनकी पूरी जिम्मेदारी भी मेरी है।

मुजफ्फरनगर से आए स्काउट्स-गाइड्स का दल 22 नवंबर से 30 नवंबर तक मंत्री आवास पर ही ठहरा हुआ है। आवास, भोजन, परिवहन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था मंत्री अग्रवाल ने अपने प्रत्यक्ष निर्देशन में सुनिश्चित की है। बच्चों और प्रशिक्षकों ने मंत्री द्वारा किए गए इस विशेष सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने स्काउट्स-गाइड्स संगठन को देश का सबसे अनुशासित और संस्कारित युवाओं का समूह बताते हुए कहा कि योगी सरकार युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण का आधार मानती है।

उन्होंने कहा, स्काउट्स-गाइड्स देश सेवा, अनुशासन और चरित्र निर्माण की भावना के प्रतीक हैं। प्रदेश सरकार ऐसे युवाओं को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस वर्ष आयोजित 19वीं नेशनल जम्बूरी में चार देशों के कुल 34,500 स्काउट्स एवं गाइड्स प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मुजफ्फरनगर का दल विभिन्न प्रतियोगिताओं, गतिविधियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में अनुशासन व सहभागिता के नए मानक स्थापित कर रहा है।

हैवानियत की शिकार हमीरपुर की नाबालिग ने तोड़ दिया दम

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

हमीरपुर। हमीरपुर जिले में दुष्कर्म की शिकार 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की एक माह तक जीवन और मौत के बीच जूझने के बाद गुरुवार रात करीब दो बजे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सांसें टूट गईं। 28 अक्टूबर की रात घर में घुसकर तीन युवकों (एक नाबालिग सहित) पर उसके साथ दुष्कर्म कर तेजाब पिलाने का आरोप था। इसके बाद से पीड़िता का पूरा उपचार सफर अनिश्चितता, अव्यवस्था और लापरवाही में उलझा रहा। छह अस्पतालों की दौड़, सात बार रेफर, कहीं बेड नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं पैसा नहीं।

हर मोड़ पर परिवार टूटता गया और सिस्टम लाचार होता रहा। हालत गंभीर होने के बावजूद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसे तीन दिन तक स्ट्रेचर पर रखा गया। बुधवार को उसे बेड मिला, पर खून की कमी और देर से मिले इलाज ने गुरुवार रात उसकी सांसे छीन लीं। आरोप है कि 28 अक्टूबर की रात पीड़िता घर में सो रही थी, तभी गांव के एक

नाबालिग समेत तीन युवक घर में घुसे और उसके साथ दुष्कर्म कर तेजाब पिला दिया। परिजन उसे तुरंत सरीला सीएचसी ले गए, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

झांसी में करीब 12 दिन तक इलाज चला। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे पहली बार झांसी से पीजीआई लखनऊ रेफर किया, लेकिन वहां लंबा चौड़ा खर्च बताया गया। इसके बाद वह झांसी से उसे हमीरपुर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पीड़िता ने मीडिया के सामने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप दोहराया। मामला सामने आने पर उसे जिला अस्पताल से कानपुर हैलट रेफर किया गया, यहां लगभग 15 दिन तक उपचार चलता रहा। हालत लगातार गंभीर बनी रही।

पीड़िता को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेज दिया

इसलिए चिकित्सकों ने दूसरी बार कानपुर हैलट से पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया। पीजीआई में दो दिन तक उपचार चला और हल्का सुधार भी दिखाई दिया, लेकिन डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए पिता से दो लाख रुपये जमा करने को कहा। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पिता रकम जमा नहीं कर सके। पैसों की व्यवस्था न होने पर पीड़िता को लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। यहां भी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसे तीन दिन तक स्ट्रेचर पर रखा गया, लेकिन बेड मिला, न वार्ड, न तत्काल इलाज। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे उसे सर्जरी वार्ड में शिफ्ट किया गया।

बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में पिस्टल से चली गोली

भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी के सीने को छेद गई, मौत

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र का है जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। विवाह समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

दरअसल बुलंदशहर के ककोड़ कस्बे से शिवम की बारात चोला थाना क्षेत्र के गांव खानपुर में पहुंची थी । जहां दूल्हा शिवम मंडप के दरवाजे पर तिलक के लिए के पहुंचा ही था तभी इस दौरान लड़की के परिवार में शामिल गांव खानपुर निवासी सुग्रीव सोलंकी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि कई बार फायर करने के बाद सुग्रीव सोलंकी की पिस्टल में गोली फस गई सुग्रीव सोलंकी के द्वारा बार-बार पिस्टल का ट्रिगर दबाने के बाद भी पिस्टल नहीं चली। लेकिन अचानक पिस्टल से गोली चल गई और वहीं पास में कुर्सी पर बैठे अजय नगर निवासी

भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी के हाथ को चीरते हुए गोली सीने में जा लगी। भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी के गोली लगने के बाद शादी में अफरा तफरी मच गई तभी कुछ लोग घायल धर्मेंद्र को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए लेकिन धर्मेंद्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्मेंद्र के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उधर जैसे-तैसे शिवम के विवाह की रस्मे निभाई गई लेकिन खुशी का माहौल गम में तब्दील हो चुका था। एसपी सिटी शंकर प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।